

पत्रांक..... /
डी०एफ०पी०/एफ०१-०८/२०१४

प्रेषक,

एस० सिद्धार्थ
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०)
बिहार, पटना।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना एवं अन्य विभागीय योजनाओं के संभाव्यता प्रतिवेदन/सर्वेक्षण/परियोजना/अध्ययन मोबिलाईजेशन, सफलता एवं अनुश्रवण शुल्क के भुगतान हेतु ₹7.00 (सात) करोड़ मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :- स्वीकृत।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या 180 दिनांक 02.03.16 के क्रम में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2016-17 अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना एवं अन्य विभागीय योजनाओं के संभाव्यता प्रतिवेदन/सर्वेक्षण/परियोजना/अध्ययन मोबिलाईजेशन, सफलता एवं अनुश्रवण शुल्क के भुगतान हेतु ₹7.00 (सात) करोड़ मात्र की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. इस योजना अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र की परियोजनाओं के कन्सेप्चुलाईजेशन से लेकर कमिशनिंग तक का कार्य एम०ओ०ए० के तहत किया जाना है। यथा जागरूक उद्यमी की पहचान, स्थल चयन, एस०पी०भी० का गठन एवं चयन, तकनीक का स्रोत, बाजार लिंकेज, डी०पी०आर० तैयार कराना, योजना स्वीकृत कराना, अनुदान उपलब्ध कराना तथा सरकार को योजनाओं के प्रभावकारी क्रियान्वयन हेतु आवश्यकता आधारित परामर्श देना है। इस कार्य हेतु पी०एम०ए० को परियोजना लागत का एक प्रतिशत शुल्क के रूप में तथा शेष एक प्रतिशत का भुगतान सफलता शुल्क के रूप में परियोजना के पूरी होने पर किया जाना है।

3. कार्य की महत्ता एवं अनुदान भुगतान की प्रक्रिया के त्वरित निष्पादन को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा पी०एम०ए० के रूप में आई०एल० एण्ड एफ०एस०-सी०डी०आई० लिमिटेड, दाराशॉ एण्ड कम्पनी लिमिटेड-सुमन प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट प्रा० लि०, एस पी ए कैपिटल-हेबे फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा० लि० एवं एस आर ई आई एण्ड एफ०जी०ए०पी०एल० को पी० एम० ए० के रूप में नामित किया गया है।

4. इसके अतिरिक्त निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार निर्गत आदेश के विरुद्ध अन्य कार्यान्वयन एजेन्सी/संस्थान/संस्था को भी संभाव्यता प्रतिवेदन/सर्वेक्षण/परियोजना/अध्ययन मोबिलाईजेशन, सफलता एवं अनुश्रवण शुल्क के रूप में भुगतान किया जायेगा।

5. संबंधित संस्थान/पी०एम०ए०/अभिकरण/संस्था के द्वारा प्रस्तुत विपत्र के दावों का भुगतान सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आदेश के पश्चात् ही विपत्र की राशि की निकासी की जायेगी।

6. राशि का भुगतान वित्त विभागीय संकल्प संख्या 4308(वि०)2, दिनांक 22.06.2007 एवं 119(वि०)2, दिनांक 04.01.2008 में निहित प्रावधान तथा राज्य सरकार एवं पी०एम०ए० के साथ हस्ताक्षरित मेमोरेन्डम ऑफ एग्रीमेन्ट (MOA) के प्रावधान के अनुरूप किया जायेगा।

7. राशि का व्यय बजट मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80-सामान्य, लघु शीर्ष 102-औद्योगिक उत्पादकता, माँग संख्या-23, उप शीर्ष 0142-प्रोजेक्ट एवं फिजीविलिटी रिपोर्ट एवं परामर्शी कार्य परियोजना की तैयारी एवं परामर्शी कार्य, विपत्र कोड P2852801020142, राज्य योजना स्कीम कोड IND-5570, विषय शीर्ष 28 01 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलित होगा, जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध है।

8. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सलाहकार-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना होंगे जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि की निकासी करेंगे। संबंधित एजेन्सी/अभिकरण/ संस्थान/संस्था के विपत्र के दावों का अनुमान्य राशि का भुगतान सक्षम प्राधिकार के निर्गत आदेश के आलोक में सीधे उनके बैंक खाता में NEFT/RTGS/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध करायेगें।

9. इस योजना के मुख्य नियंत्री पदाधिकारी निदेशक (खा० प्र०), खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना होंगे। जो इस योजना का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेंगे।

क्रमशः पृष्ठ-02 पर....

10. राशि की निकासी एवं उसका समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक-4263 वि०, दिनांक-20.05.14 द्वारा निर्गत दिशा निदेश के अनुरूप की जाएगी।
11. योजना का कोड नं०-IND-5570 है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कोषागार में विपत्र प्रस्तुत करते समय तथा व्यय प्रतिवेदन में योजना कोड अवश्य अंकित करेंगे।
12. प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री, बिहार, पटना की स्वीकृति संचिका संख्या-डी०एफ०पी०/एफ०१-०८/२०१४ के पृष्ठ-७७/टि० पर प्राप्त है। जिसका गै०से०प्रे०सं०-362, दिनांक-07.12.2016 हैं।
13. राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-डी०एफ०पी०/एफ०१-०८/२०१४ के पृष्ठ-८२/टि० पर दिनांक 30.12.16 को प्राप्त है। जिसका डायरी संख्या-278/OSD, दिनांक 27.12.16 है।
14. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 8003 वि०(२) दिनांक 18.09.2008 में निहित पत्रांक 2561 वि०(२) दिनांक 17.04.1998 की कंडिका-2 एवं 15 एवं पत्रांक 2938 वि० (२) दिनांक 08.04.08 के आलोक में किया जायेगा तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
15. वित्त विभागीय पत्रांक:-2561/वि०(२), दिनांक:-05.10.2007 के आलोक में इस राशि की निकासी में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से
ह०/-
(एस० सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक...../
डी०एफ०पी०/एफ०१-०८/२०१४

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(एस० सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक...../
डी०एफ०पी०/एफ०१-०८/२०१४

प्रतिलिपि- सलाहकार-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना को (दो प्रतियों) में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(एस० सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक...../
डी०एफ०पी०/एफ०१-०८/२०१४

प्रतिलिपि- निदेशक (खा० प्र०), निदेशक खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(एस० सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक...../
डी०एफ०पी०/एफ०१-०८/२०१४

प्रतिलिपि- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, ह० एवं रे० निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना/आय-व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/ बजट शाखा, उद्योग विभाग/आई०टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-3(उ०नि०)/ प्रशाखा-1 योजना (स०)/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12
10/11/2017
(एस० सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।